RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-04
April-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

सर्व शिक्षा अभियान– भारत में शिक्षा की एक सफल योजना

[1]Sadhana Kumari and [2]Dr Suman Sharma

[1]*Research Scholar OPJS University Churu Rajasthan*
[2]*Associate Professor OPJS University Churu Rajasthan*

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 02 April 2018

Keywords
सर्व शिक्षा अभियान, उपलब्धि, शिक्षा, भारत

ABSTRACT

सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2001 में प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। योजना का मुख्य फोकस प्राथमिक स्तर के स्कूल जाने वाले बच्चों में नामांकन, उपस्थिति को बढ़ाना और ड्रॉप–आउट को कम करना था। उपरोक्त लक्षित उद्देश्यों में भाग लेने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई शैक्षिक पहल शुरू की गईं।

शिक्षा को आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और समृद्धि की आधारशिला भी माना जाता है। यह बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान देता है। शिक्षा न केवल जीने के लिए प्रत्यक्ष महत्व है (किसी व्यक्ति की धारणा और विचार के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए), यह मानव क्षमता के अन्य अधिकारों के रूपांतरण को भी प्रभावित कर सकता है। शिक्षा व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी वृद्धि में मदद करती है, यह उसकी जन्मजात क्षमताओं को विकसित करती है, उसके व्यक्तित्व का विकास करती है, व्यवहार को संशोधित करती है, उसे समाज में अपने साथी के साथ समायोजन का घाव सिखाती है और उसे एक अच्छा नागरिक तैयार करती है।

प्रस्तावना

90 के दशक ने स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों और संस्थानों के समानांतर चलने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखा है। इसके लिए बीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति –1986 (NPE–1986) पर बोए गए थे जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण (न्म्) स्कूल प्रणाली या गैर–औपचारिक शिक्षा (छथ्) के समानांतर धारा के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। । इस प्रवृत्ति को 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) स्थापित करने के सरकार के निर्णय द्वारा आगे बढ़ाया गया था। एक बहुप्रतीक्षित यूईई मिशन एनएलएम के बजाय एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के मुद्दे से राजनीतिक ध्यान हटाने में सफल रहे। शिक्षा। 1993 में, सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) के तहत सरकार ने एनएलएम के दरवाजे 9–14 आयु वर्ग के लिए खोले, बजाय इसे 15–35 आयु वर्ग तक सीमित करने के जैसा कि मूल रूप से इरादा था। इस कदम का तात्पर्य यह है कि सरकार उच्च प्राथमिक स्तर (वर्ग अप–अपप) पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती है जहाँ तक नीति का संबंध है, यह सब अस्तित्व में नहीं हो सकता है। जब सीबीएसई ६ राज्य के मानदंडों के अनुसार औपचारिक स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला विज्ञान आयाय अकेले साक्षरता के पर्याप्त होने की उम्मीद थी। इस विकास के परिणामस्वरूप, राज्य की शैक्षिक जिम्मेदारी को पूरा किया जा रहा है यदि 6–9 वर्ष की आयु के एक बच्चे को एनईएफ केंद्र में तीन साल बिताए जाते हैं, उसके बाद वयस्क साक्षरता वर्ग में दो साल की कवरेज की जाती है। 9–11 साल की उम्र में कभी बिना स्कूल गए भी।

ईएसएस इन साक्षरता परियोजनाओं में सबसे पुराना था, जिसे नवंबर 1991 में शुरू किया गया था। इस परियोजना ने 20–69 प्रतिशत की उपलब्धि पर सूचना दी और इसी तरह 1992 में दिल्ली प्रशासन के ईएफए कार्यक्रम को बिना किसी प्रगति की रिपोर्ट के प्रसारित किया गया और डीएसएस को प्रसारित किया गया। 1993. छक्डब परियोजना भी 1995 में 17. 18 प्रतिशत की अल्प उपलब्धि के साथ समाप्त हुई। अब भारत के केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए 6–14 वर्ष के बाल आयु समूह के लिए एक प्रोग्रामर एसएसए (7 वर्ष की गुणवत्ता वाली शिक्षा) है। इनमें से किसी भी परियोजना का मूल्यांकन बाहरी रूप से नहीं किया गया था। वास्तव में, सभी तीन परियोजनाएं 60 प्रतिशत आवश्यकता की उपलब्धि दर से काफी नीचे थीं, जो बाहरी मूल्यांकन शुरू करने के लिए आवश्यक है। अब तक साक्षरता और सतत शिक्षा (पीएल एंड सीई) परियोजनाएं पहले की परियोजनाओं का हिस्सा रही हैं।

सर्व शिक्षा अभियान समिति ने अपने साक्षरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्अभियान दृष्टिकोणश को अपनाया था। अभियान का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से मत स्वयंसेवक 'आधारित दृष्टिकोण है, जिसके लिए प्रत्येक दस शिक्षार्थियों के लिए एक स्वयंसेवक की आवश्यकता होती है। एक बड़े लक्ष्य के लिए, प्रत्येक अभियान को हजारों शिक्षित स्वयंसेवकों की आवश्यकता थी। इस प्रकार स्वयंसेवक और उनकी प्रोफाइल सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से हैं, जिन पर हर अभियान की सफलता या विफलता निर्भर है। अब दिन की पढ़ाई छोड़ने वाली बच्ची हमारे स्कूल शिक्षा प्रणाली की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए एक वैकल्पिक प्रणाली (शिक्षण केंद्र) सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए होनी चाहिए,

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

खासकर जो स्कूलों से बाहर हैं। इस प्रकार यह अध्ययन में महत्वपूर्ण था कि नव–साक्षर छात्रों के प्रोफाइल और विचारों की समीक्षा उनके बेहतर शिक्षण के संबंध में की जाए।

सर्वशिक्षा अभियान का प्रभाव

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान एक बहुत व्यापक और प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहल शामिल हैं। जहां तक मात्रात्मक पहलों (फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर) का संबंध है, इसमें शामिल हैंय नए स्कूल खोलना, पुराने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, चारदीवारी का निर्माण, फर्नीचर, पुस्तक, ड्रेस सामग्री प्रदान करना आदि। लेकिन गुणात्मक पहल के उपायों में नामांकन से संबंधित संकेतक, जैसे प्रतिधारण, उपस्थिति और ड्रॉपआउट कम करना शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विकास पर एसएसए के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, नामांकन, उपस्थिति और ड्रॉप–आउट दर जैसे तीन प्रमुख चर उपरोक्त संकेतकों से बाहर खाते में लिए जाते हैं। योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, 5 साल (2012–2017) को कवर करने वाली टाइम सीरीज के आंकड़ों पर चर्चा की गई।

1. छात्रों का नामांकन

स्कूल जाने वाले बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए एक बड़े उद्देश्य के साथ सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। यह खंड 2012–17 से पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रों के नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर का विश्लेषण करता है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभिक शिक्षा के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है क्योंकि इस योजना ने स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें और ड्रेस सामग्री जैसी कई सुविधाएं दी हैं। ये सुविधाएं गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े और आदिवासी लोगों के लिए बहुत सहायक हैं।

2. छात्रों की उपस्थिति

सीखने के लिए मात्र नामांकन पर्याप्त नहीं है। बेटर्स ऑफ लर्निंग के लिए, छात्रों की उपस्थिति की दर को बढ़ाने के लिए नियमित उपस्थिति बहुत आवश्यक है। मध्याह्न भोजन (एमडीएम) सहित कई शैक्षिक प्रचार योजनाएँ भारत सरकार द्वारा संचालित की गई थीं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान ने छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि की है क्योंकि इसने स्कूलों में छात्रों को मुफ्त ड्रेस, किताबें, मध्याह्न भोजन जैसी कई सुविधाएं प्रदान की हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोग इस योजना से प्रभावित हैं। इस योजना ने अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में माता–पिता की चेतना को भी बढ़ाया है।

योजना की संचालन संबंधी समस्याएं

छात्रों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि के बावजूद यह योजना परिचालन बाधाओं से मुक्त नहीं है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाएँ अपेक्षा के स्तर तक नहीं हैं। हालांकि कई स्कूलों ने अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि की है, फिर भी गैर–बहुमत वाले स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं, अपर्याप्त कमरे हैं। छात्र वर्ग के कमरे का अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है। कई स्कूल अभी भी सुरक्षित पेयजल सुविधा, बिजली कनेक्शन और शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। यद्यपि भौतिक और अवसंरचनात्मक सुविधाओं में कुछ सुधार पाए जाते हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक दूरी का सपना बनकर रह गई है। यह पाया जाता है कि शिक्षकों को कई गैर–शैक्षणिक गतिविधियों जैसे किताबों का वितरण, ड्रेस सामग्री, उपयोग प्रमाणपत्र तैयार करने और रिकॉर्ड बनाए रखने से पहले से कब्जा कर लिया जाता है। कई स्कूलों के शिक्षकों ने स्कूल के अंदर होने वाले निर्माण कार्यों की समग्र निगरानी का काम सौंपा है। गैर–शैक्षणिक गतिविधियों के ये सभी बोझ शिक्षकों की दक्षता को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें कक्षाओं को उलझाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कम समय मिल रहा है। कुछ स्कूलों में स्टाफ की कमी के कारण शिक्षण और सीखने का माहौल बर्बाद हो गया है। फील्ड विजिट के दौरान पाया गया कि कई स्कूलों में एक ही शिक्षक एक से पांच तक की क्लास ले रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, गैर–शैक्षणिक कार्यों में प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता और शिक्षकों के पूर्व–कब्जे के कारण गुणवत्ता शिक्षा एक प्रमुख कारण बन गया है। अभियान पर्यवेक्षण और प्रशासनिक समस्याओं से भी ग्रस्त है। योजना का कोई नियमित पर्यवेक्षण नहीं है क्योंकि योजना के संचालन के प्रभारी अधिकारी अन्य सरकारी गतिविधियों में अत्यधिक व्यस्त हैं। ऊपरी स्तर पर योजना के संचालन के संबंध में अधिकारियों के बीच खराब सहयोग और समन्वय है। जिला स्तर से लेकर स्कूल स्तर तक के अधिकारी अपने दैनिक कार्यों से आगे निकल जाते हैं और योजना का संचालन ठीक से देखरेख करने के लिए बहुत कम समय पाते हैं।

निष्कर्ष

भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की माँग बढ़ रही है। साथ ही यह देखा गया है कि सभी को शिक्षित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन और कार्य को अलग–थलग नहीं किया जा सकता है। इसे राज्य और केंद्र सरकार, निजी संगठनों और स्थानीय सरकार के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयास वास्तव में उन संकेतकों को विकसित करने में सक्षम हैं जो एक विकसित देश के प्रदर्शन का आकलन करने की कसौटी हैं। आने वाले वर्ष निश्चित रूप से भारत को विकासशील देशों

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

के लिए एसएसए जैसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक आदर्श बनाने के लिए मूल्यवान होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, जे.सी. (2003)। ष्आधुनिक भारतीय शिक्षा, इतिहास शिक्षा समस्याए, क्षिप्रा प्रकाशन नई दिल्ली।
2. ड्रेज, जे। और सेन, ए। (1995)। ष्बुनियादी शिक्षा राजनीतिक मुद्दे के रूप में शैक्षिक योजना और प्रशासन, पत्रिकाओं के जर्नल। दिल्ली
3. ड्रेज, जे। और सेन, ए। (1995)। ष्राजनीतिक मुद्दों के रूप में बुनियादी शिक्षा शैक्षिक योजना और प्रशासन के जर्नल, VolNo.1, श्रंद, NIEP।, नई दिल्ली।
4. द्विवेदी, आर। (2016)। ष्भारत में शिक्षा का विकासए, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत
5. घई, के.के. (2016)। ष्फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्सए, कल्याणी पब्लिशर्स, लुढिनिया, नई दिल्ली।
6. कुरियन, जे। (1978)। "भारत में प्राथमिक शिक्षा, मिथक वास्तविकता, वैकल्पिकए, विकास प्रकाशन हाउस। प्राइवेट
7. मंगल, एस। के। (1991)। ष्आउंड वर्क ऑफ एजुकेशनष लोटस प्रेस नई दिल्ली।
8. माथुर, एस.एस. (2010) भारतीय शिक्षा राउटलैड नई दिल्ली। 9. पाइल, एम.वी. (2070)। ष्भारत के संविधान का परिचय विकास प्रकाशन हाउस।
9. मणिमारन, जी और आनंदन, के (2009), प्राथमिक शिक्षकों की राय गतिविधि–आधारित शिक्षण, जर्नल एडट्रैक, वॉल्यूम –9, नंबर –4 के लिए
10. नीलकमल प्रकाशन हैदराबाद। मिश्रा, लोकनाथ (2005), चतुर्थ श्रेणी के छात्रों के गणित में कम उपलब्धि के कारण, जर्नल एडट्रैक, वॉल्यूम –1, नंबर –4
11. नीलकमल प्रकाशन हैदराबाद। NCERT (2000)। शैक्षिक अनुसंधान, प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली का पांचवा सर्वेक्षण।
12. सक्सेना, ए.बी. (2000)। "नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य और प्रक्रियाष जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन वॉल्यूम–XXVI नंबर 2 प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved